भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 548
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कालीकट हवाई अड्डे पर आरईएसए कार्य

548. श्री एम.के.राघवन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मंत्रालय ने कालीकट हवाई अड्डे पर आरईएसए निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है;
(ख) यदि हां, तो टेंडर दिए जाने की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इतने व्यापक विलंब के कारण क्या हैं;
(ग) कालीकट हवाई अड्डे पर आरईएसए निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) उक्त हवाईअड्डे पर पूरे किए गए आरईएसए कार्य से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरईएसए कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): कालीकट हवाईअड्डे पर दुर्घटना पर विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा गठित विमानन विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कालीकट हवाईअड्डे पर रनवे के दोनों सिरों पर 240 मीटर के रनवे एंड सेफ्टी एरिया (आरईएसए) का प्रावधान करने के लिए केरल राज्य सरकार को 14.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार ने दिनांक 19.10.2023 को एएआई को 12.54 एकड़ जमीन सौंप दी है। कालीकट हवाईअड्डे पर रनवे के दोनों सिरों पर 240 मीटर के रनवे एंड सेफ्टी एरिया (आरईएसए) के विकास का कार्य दिनांक 19.02.2024 को अवॉर्ड किया गया है और केरल राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिए पर्यावरण मंजूरी दिनांक 11.07.2024 को जारी की गई है।

कालीकट हवाईअड्डे पर वाइड बॉडी विमान के परिचालन की लाभप्रदता और साध्यता को ध्यान में रखते हुए, एएआई ने एक विशेष उपाय के रूप में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आरईएसए के प्रावधान के लिए भूमि को भरने और समतल करने की लागत वहन करने की पेशकश की है। एएआई द्वारा आरईएसए प्रावधान के लिए 484.57 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी दी गई है।

(ङ) : कार्य पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा दिसंबर, 2025 है। तथापि, वास्तविक समय-सीमा विभिन्न कारकों जैसे अनिवार्य अनुमतियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि पर निर्भर करती है।

*****